



"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेडेले फिलिपा

# दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 18 अप्रैल 2026 शनिवार

## सम्पादकीय

### नशे का जाल और युवा पीढ़ी

देश में महानगरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में नशीले पदार्थों का जाल लगाता फैलाता जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा और गहरा प्रभाव युवा वर्ग पर पड़ रहा है, जो उनके भविष्य और जान दोनों को खतरों में डाल रहा है। यह केवल व्यक्तिगत ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बड़ी चुनौती बन गया है। युवाओं के सामूहिक रूप से नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने के लिए विशेष आयोजन की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। मगर, अब इस तरह के आयोजनों का स्वरूप भी बदल रहा है।

एसी ही एक घटना हाल ही में मुंबई के गोरगांव में सामने आई, जहां नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से प्रबंधन संस्थान में भेजा जाने वाले दो विद्यार्थियों की मौत हो गई। ये दोनों अपने दोस्तों के साथ एक संगीत कार्यक्रम में आए थे। सवाल है कि जब नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री और खरीद के खिलाफ कानून में सख्त प्रावधान है, तो फिर युवाओं की इन तक आसानी से पहुंच कैसे संभव हो पा रही है?

यह बात ठीक नहीं है कि नशीले पदार्थों की बिक्री और इनके सेवन के लिए नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। रेव पार्टी की बजाय अब संगीत कार्यक्रमों की आड़ में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। पुलिस को मालूमिक, गोरगांव में संगीत कार्यक्रम में भाग लेते आए जिन दो छात्र-छात्री की मौत हुई, वे पहले से नशा करके आए थे और उन्होंने कार्यक्रम के दौरान किए से नशीले पदार्थों का सेवन किया।

यह वेदद विचारजगत् है कि पिछले कुछ वर्षों में मनोरंजन की आड़ में युवाओं में नशाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार और प्रशासन के स्तर पर गंभीरता में प्रयास करने की इच्छाशक्ति कहीं नजर नहीं आती है। जबकि युवाओं में नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति से आपराधिक घटनाओं भी लगातार बढ़ रही हैं। हेराणी की बात है कि मुंबई जैसे महानगर में संगीत कार्यक्रमों की अनुमति देने से पहले प्रशासन की ओर से जांच और निगरानी की जरूरत महसूस नहीं की जाती है। जब तक सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सामाजिक स्तर पर सतर्कता नहीं बढ़ती जाएगी, तब तक यह समस्या हल नहीं हो पाएगी।

आमतौर पर नशा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मानसिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। यह आदत कब तक में तबतक हो जाए, पता नहीं चलता। आपस को एक नकारात्मक अवधारणा के तौर पर देखा जाता है, जबकि लत या व्यसन एक नकारात्मक अवधारणा है। यह एक मनोवैिकार है, क्योंकि जिस नशे के सेवन की लत लग जाए, उसके बिना जीवन की निरंतरता असंभव दिखाई देती है। आदत बदलना संभवतः आसान हो सकता है, पर लत से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल लगता है।

### परिसीमन और आशंकायें

इसमें कोई दो राय नहीं कि संसद में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी समय की जरूरत हो सकती है और निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसमें बदलाव हो सकता है। मगर इस वर्ष परिसीमन की कवायद को लेकर कई सवाल उभरते दिख रहे हैं। खासतौर पर दक्षिण भारत के राज्यों की ओर से यह आशंका जताई जा रही है कि परिसीमन के ताजा प्रस्ताव के तहत जो प्रथम समने आया है, अगर वह अमल में आया तो यह व्यापक स्तर पर मेदभाव का कारण बनेगा।

हालांकि इस तरह के कदम उठाने से पहले देशभर में सर्वसम्मति कायम करने की अपेक्षा की जाती है, ताकि राज्यों के बीच मतभेद न उजागे, लेकिन परिसीमन को लेकर कई सरकारों की बीच तमिलनाडु में जिस तरह का विवाद उभर रहा है, उससे कई सवाल उठे हैं। तमिलनाडु है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुजरात को केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन की कवायद के खिलाफ विरोध की लड़ करके हुए इससे संबंधित विधेयक को प्रति जता कर और काका झंडा दिखा कर पूरे राज्य में आंदोलन की शुरुआत कर दी। इससे पहले स्टालिन ने यहां तक कहा था कि तमिलनाडु की विंता को दूर किए बिना अगर परिसीमन को आगे बढ़ाया गया, तो राज्य में एक समय बले हिंदी विरोधी आंदोलनों जैसी स्थिति बन सकती है।

निश्चित रूप से इस संवेदनशील मुद्दे पर देश के अलग-अलग राज्यों में इस तरह के मतभेद पैदा नहीं होने चाहिए थे और इससे जुड़ी विंताओं का समाधान वक्त की जरूरत है। मगर हेराणी की बात यह है कि क्या केंद्र सरकार को इतना आसाम नहीं था कि लोकसभा में सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के क्रम में उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच जिस तरह का असंतुलन पैदा होने वाला है, उससे कई स्तर पर असंतोख उत्पन्न सकता है। दरअसल, सरकार परिसीमन को महिला आरक्षण में इस मसले पर व्यापक असंतोख उत्पन्न रहा है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल आदि राज्यों में भी परिसीमन में आबादी के आधार पर लोकसभा की सीटों में वृद्धि होने पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दक्षिण भारतीय राज्यों को परिवार नियोजन को लेकर बेहतर प्रदर्शन का खमियाजा उठाना पड़ रहा है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि स्टालिन ने परिसीमन संशोधन को दक्षिणी राज्यों के खिलाफ और देश की प्रगति में योगदान देने की सजा तक कहा है।

सवाल है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर केंद्र सरकार को सभी राज्यों को विश्वास में लेने की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। एक यह यह है कि परिसीमन का मुख्य आधार चूक जिनगणना होता है, तो नई विधियां हैं इससे संबंधित किसी कवायद पर उठने वाले सवालों का हल क्यों नहीं निकाला गया? कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि अगर परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो इस मसले पर उभरने वाली आपत्तियों पर गौर किया जाए और सभी राज्यों के बीच समझौते कायम की जाए।

# आम आदमी के निशाने पर खास आदमी



### -शिवनाथ सचदेव-

पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की सरकार ने विशिष्ट संस्कृति वाली मानसिकता के खिलाफ आदेश दिया है कि मंत्रियों की कारों के काफिले नहीं चलेंगे, उनकी कारों सायनर नहीं बजाएंगी, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दंड मिलेगा। बच्चे, चाहे वे मंत्री के हों या अफसर के, सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे।

खरब मध्य प्रदेश के रायसेन में सांची रोड पर हुई एक सड़क-घुर्घटा की है। इस दुर्घटना में एक पत्रकार की मृत्यु हो गयी। बताया जा रहा है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए सप्तर पर पहुंचने नहीं मिल पायी, अन्धध करणकारी शायद जान बच सकती थी। इस तरह की कोई अनौखी घटना नहीं है। अक्सर होता रहता है ऐसा। अक्सर आम आदमी को पहुंचले-सेवा का समय पर लाभ नहीं मिल पाता। अक्सर मंत्रियों की कारों के काफिले सायनर बजाते, ए लु उड़ते आम आदमी को अंतुंग दिखाते, सड़कों पर आगे निकल जाते हैं। लाल और नीली बलियां वाले यह काफिले उस संस्कृति का एक सेहरा हैं जिसे आम बोल-बाल की भाषा में 'वीआईपी कल्चर' यानी विशिष्ट लोगों की व्यवस्था कहा जाता है।

राजनीति में इस व्यवस्था का चेहरा अक्सर दिख जाता है। मंत्रियों के कारों को किसी सचवाक का सामना



न करना पड़े, इसके लिए आम जनता की कारें कहीं भी, और कभी भी, रोकनी जा सकती हैं। पुरुखा के नाम पर ऐसी व्यवस्था की गयी है कि किसी मंत्री की कार को अकेले कहीं आना-जाना न पड़े। उनकी गाड़ी के आगे भी गाड़ियां होती हैं, पीछे भी। नाना जातियां हैं इससे शासक का मानवा बढ़ता है।

इसी रुतबे का नाम है वीआईपी कल्चर यानी विशिष्ट जनों वाली राजनीतिक संस्कृति। इस संस्कृति की पहचान सिर्फ कारों का काफिला नहीं होती। बड़े लोग 'कई-कई' तर्कों से अपना बड़ा होना सिद्ध करने की कोशिश में लग रहे हैं।

कथित बड़े लोगों के बच्चे सरकारी अस्पतालों में नहीं पैदा होते। उनके लिए शानदार और महंगे अस्पतालों हैं। यह बच्चे सरकारी अस्पतालों में भी नहीं पढ़ते। सरकारी स्कूल तो आम आदमी के लिए होते हैं। आम आदमियों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल हैं जहां न बच्चों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था होती है न टीक-ठाक दिखने वाले स्कूलों हैं। अक्सर ऐसे खस्ता होल स्कूलों के बारे में समाचार नहीं मिलते, प्रसारित होते रहते हैं, पर स्थिति में

कोई परिवर्तन आता नहीं दिखता। नाना जातों के कि उसका प्रभाव बड़ा हो ही नहीं, बड़ा दिखे भी। बड़ा दिखने की यह लालसा ही 'वीआईपी कल्चर' को जन्म देती, उसे पालती-पोसती है। मजे की बात यह है कि इस लालसा की अक्सर आलोचना होती है, इसे समाप्त करने के बड़े और दावे भी किये जाते हैं, पर व्यवहार में ऐसा होता नहीं दिखता। दिखना चाहिए। हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की नयी सरकार ने एक रास्ता दिखाया है इस विशिष्ट 'संस्कृति' वाली मानसिकता को समाप्त करने का। इसी मार्ग, 2026 में वहां चुनाव हुए थे। इस चुनाव के बाद एक ऐतिहासिक बदलाव आया है वहां की राजनीति में। देश के नये और युवा प्रशासनी, 36 वर्षीय बालेन शाह, ने दशकों पुराने राजनीतिक दलों का विचार ही समाप्त नहीं किया, एक समातवादी राजनीतिक संस्कृति को स्थापित करने का संकल्प भी लिया है। देश में आशर जारी कर दिया है कि मंत्रियों की कारों के

ही नहीं रहता, लगातार इस कोशिश की भी रहता है कि उसका प्रभाव बड़ा हो ही नहीं, बड़ा दिखे भी। बड़ा दिखने की यह लालसा ही 'वीआईपी कल्चर' को जन्म देती, उसे पालती-पोसती है। मजे की बात यह है कि इस लालसा की अक्सर आलोचना होती है, इसे समाप्त करने के बड़े और दावे भी किये जाते हैं, पर व्यवहार में ऐसा होता नहीं दिखता। दिखना चाहिए। हमारे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल की नयी सरकार ने एक रास्ता दिखाया है इस विशिष्ट 'संस्कृति' वाली मानसिकता को समाप्त करने का। इसी मार्ग, 2026 में वहां चुनाव हुए थे। इस चुनाव के बाद एक ऐतिहासिक बदलाव आया है वहां की राजनीति में। देश के नये और युवा प्रशासनी, 36 वर्षीय बालेन शाह, ने दशकों पुराने राजनीतिक दलों का विचार ही समाप्त नहीं किया, एक समातवादी राजनीतिक संस्कृति को स्थापित करने का संकल्प भी लिया है। देश में आशर जारी कर दिया है कि मंत्रियों की कारों के

काफिले नहीं चलेंगे, सड़कों पर दौड़ती उनकी कारें सायनर नहीं बजाएंगी, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाला बच्चे कोई भी हो, उसके साथ कानून एक जैसा व्यवहार करेगा। एक बड़ा बदलाव यह भी है कि अब नेपाल में बच्चे, चाहे वे मंत्री के हों या संत्री के, सामूहिक कर्मचारियों के अथवा किसी अफसर के, सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, और यदि सफल हो जाता है तो छोटा-सा देश नेपाल समातवादी समाज की रचना की दिशा में एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करेगा।

अक्सर इस तरह की लोक-लुभावण घोषणाएं शासक-वर्ग करता है। हमारे देश में भी कई बार

इस तरह की घोषणाएं होती रही हैं, पर देखा यह भी गया है कि जल्दी ही घोषणाएं भुला दी जाती हैं। कुछ साल पहले ही जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो बड़े जोर-शोर से यह घोषणा हुई थी कि आम आदमी पार्टी के मंत्री बड़ी-बड़ी कारों में नहीं चलेंगे, बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे। उनके बच्चे आम सरकारी स्कूलों में शिक्षा पायेंगे, उनके इलाका सरकारी अस्पतालों में होंगे। पर जल्दी ही इन घोषणाओं का मुल्लासा उतर गया। मंत्री बड़े-बड़े बंगलों में पहुंच गये, तीन कमरों के मकान में रहने वाले मुख्यमंत्री के लिए 'श्रीशमल' बन गया। लालचरी वाली कारों के काफिले सड़कों पर दौड़ने लगे। पार्टी के मानस ही आम आदमी से जुड़ा हो, पर सरकार खास संस्कृति वाली ही बनी रही। आवश्यकता है इस खास संस्कृति की मानसिकता के खिलाफ उठ खड़े होंगे की। सही मायनों में बीमार है यह

## मनुष्यता और महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा



### -डा. वीरेन्द्र आजम-

जब स्कूल निशाना बनते हैं तो ज्ञान भरता है। जब अस्पताल मलबे में बदलते हैं तो करुणा दम तोड़ती है, और जब तेल-गैस संयंत्र जलते हैं तो जीवन का ईंधन समाप्त होता है। सच तो यह है कि यह केवल युद्ध की नहीं, मानवता की पराजय है। परती पर इंसायनियत फिर लखलुहान है। दुनिया बाबूद की गुएं में संसार ले रही है, बाबूद के हुए में बच्चों की हंसी, स्कूलों की चटियां और अस्पतालों की शांति सब कुछ घुल गया है। अमेरिका, इराकल और इरान के युद्ध ने सभ्यता के मुंह पर एक बड़ा काका घिसा छोड़ दिया है। युद्ध के दौरान जिस तरह बमबारी हुई है उससे मही तबाही और राष्ट्रपू को संनकरभे रथानों में संवेदना की सारी सीमाएं तोड़ दीं हैं। अब युद्ध केवल सीमाओं का नहीं रहा, बड़े विचारों, अर्थव्यवस्था और नैतिक मूल्यों पर भी आक्रमण कर चुका है। ईरान, अमेरिका, इराकल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस-यूक्रेन, हर मोर्चे पर निर्दोषों का लूटू बहा है और महाशक्तियों हथियारों के व्यापार में लिपट हैं। यदि सभ्यता का अंत युद्ध की बूल और बारूदी घुर में ही होना है, तो फिर विकास का अर्थ क्या रह जाएगा?



अमानवीयता का एक और अत्याय जोड़ दिया है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान की सरहद पर भी अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर बम बरसे हैं। पाकिस्तान ने पिछले महीने अफगानिस्तान की राज्ताली काबुल में ओमिद नया मुक्ति अस्पताल को एक बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया। हमले में करीब 2400 लोगों की मौत हो गयी और सैकड़ों लोग घायल हुए। इसके अलावा भी हिदायशी इलाकों और स्कूलों पर हमले हुए हैं। इन घटनाओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आशिर यह युद्ध किसके लिए है और किसके खिलाफ है? यह सिर्फ बच्चियों और मरीजों की मौत का आंकड़ा नहीं है अविभू मनुष्यता का शोकगीतक है। ये घटनाएं इस सदी की सबसे बड़ी शर हैं जो मानवता और नैतिकता के माथे पर गाढ़ा ढाबू बरस दज हो चुकी हैं।

हास्यास्पद बात यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इन हतनातों से फलता झाड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तो शुरु में एक बचकाना हमले दते हुए यहां तक कह दिया था कि स्कूल पर ईरान ने युद्ध बम गिराया है। लेकिन बाद में राजनीतिक बचाव करते हुए कहा गया कि निशाना सक्ते में चूक हो गई है। उपर पाकिस्तान का अस्पताल भी हमले से इनकार भी उठाना ही मनाया और खोखला है, जिनात सूरज की रोशनी में अंधकार की बात करना। सवाल यह नहीं कि बदन किसने दबाया, सवाल यह है कि मरे कौन। उत्तर स्पष्ट है-बच्चे, बीमार, और निंदेध नागरिक। राष्ट्रपक्षियों की निद, तानाशाही प्रवृत्ति और शांति की होड ने यह सिद्ध कर दिया है कि आ उन्मिद युद्ध में युद्ध अब सीमा की नहीं बल्कि सनक और अहंकार की राजनीति है।

## बस्ती विकास प्राधिकरण

संख्या-113 / ब०वि०शा०ब०वि० / 2026-27 दिनांक-17.04.2026

## सार्वजनिक सूचना

श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री चौथीराम गाटा सं०-313 ग्राम-खीरीघाट तप्पा-हवेली परगना बस्ती पूव जनपद बस्ती द्वारा उक्त गाटे में क्लीनिक के निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र संख्या-BSDA/BP/25-26/0297 की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। पक्ष द्वारा उक्त भूखण्ड में क्लीनिक के उपयोग हेतु निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त स्थल का भू-उपयोग बस्ती महायोजना-2031 (भाग-क) के अन्तर्गत व्यवसायिक 12 मी० सड़क के अन्तर्गत आता है। बस्ती महायोजना 2031 (भाग-क) में दिये गये जोनिंग रेगुलेशन एवं मॉडल भवन निर्माण एवं विभाजन उपविधि-2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में भू-उपयोग जोन्स 15.3.2 में विभिन्न क्रियाओं की अनुमत्या से सम्बन्धित जोन मैट्रिक्स 5.6 में (व्यवसायिक) भू-उपयोग के अन्तर्गत शैय्या रहित चिकित्सा क्लीनिक सामान्यतः अनुमत्य है।

मॉडल भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन में शासन के निर्गत आदेश दिनांक-21.11.2025 के अनुसार जोनिंग नियम अध्याय 18 के प्रस्तर 15.1.3 समाघात शुल्क में नियमानवली 2024 का संदर्भ है, जिसमें 15 दिन की अवधि निर्धारित है। प्रस्तर 15.1.3 (IV) महायोजना भू-उपयोग अथवा अनुमोदित ले-आउट में परिभाषित भू-उपयोग के अतिरिक्त अन्य क्रियाओं की अनुज्ञा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जनता से आपत्ति / सुझाव करने के उपरांत दी जायेगी।

यदि उक्त भूमि पर क्लीनिक के निर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृति किए जाने में किसी को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अंदर साक्ष्यों सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अथवा बस्ती विकास प्राधिकरण, बस्ती के कार्यालय में दर्ज करा सकता है, 15 दिवस की अवधि के उपरांत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को कोई विचार नहीं किया जाएगा एवं नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही कर दी जायेगी।

## सचिव बस्ती विकास प्राधिकरण, बस्ती



